

6-2-20 तकील उभयपक्ष उपस्थित बहस
प्राथी द्वारा संशोधित खाले
पत्र किमा शाकेल पत्रावली किमा
उभय पक्ष हेतु सख्त वाद
पत्रावली नम्बर 98/258
पर दिनांक 27-2-20 को
पेश हो।

27.02.2020 उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्राथी व अप्राथी संख्या 1 व 2 के नाम संयुक्त खाते की भूमि चक 1 एम.ओ.डी. पटवार इल्का मक्कासर के खाता संख्या 9/6 की कुल 3.251 हैक्टर मध्य गैरसुमकिन भूमि में से पत्थर नम्बर 98/258 (57) के किला नम्बर 16 में एक बिरसा रास्ता स्वीकृती हेतु निवेदन किया है।

अप्राथीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब का भी अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि जबाब प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है, कि पक्षकारान के मध्य खाता विभाजन का वाद औमप्रकाश आदि बनाम मुखराम वाद संख्या 131/2014 विचाराधीन है। संयुक्त खाता की भूमि में प्राथी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकारी नहीं है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की समायत बहस पर मनन किया गया पत्रावली के अवलोकन से पाया कि पक्षकारान के मध्य एक अन्य खाता विभाजन का वाद औमप्रकाश आदि बनाम मुखराम वाद संख्या 131/2014 विचाराधीन है, जो वर्तमान में प्रार्थना पत्र बहस विचाराधीन है।

प्राथी द्वारा वादे गये अनुतोष के सन्दर्भ में राजस्व अभिलेख का अवलोकन से पाया गया कि प्राथी तथा अप्राथीगण की सह खातेदारी भूमि में से प्राथी द्वारा अपने ही सहखातेदार से रास्ते की मांग की गई है।

चुकि प्राथी और अप्राथीगण संयुक्त खातेदार है। क्योंकि संयुक्त खाते में प्रत्येक काश्तकार का संयुक्त खाते की भूमि में प्रत्येक इन्च पर अपने हिस्सा अनुसार ही हिस्सेदारी होती है। इस कारण किसी भी किला विशेष पर किसी एक काश्तकार का कब्जा नहीं माना जा सकता।

यदि किसी सहकाश्तकार को किला विशेष के लिये पृथक से यदि रास्ता स्वीकृत करवाया जाना हो तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत खाता विभाजन करवाकर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 18 ता 21 के तहत रास्ते, खाले की सुविधा प्राप्त करने का अधिकारी है। जिराके सन्दर्भ में उभयपक्ष के मध्य वर्तमान में वाद विचाराधीन है। इस कारण प्राथी अपने सहखातेदारान से संयुक्त खाते की भूमि में से किला विशेष हेतु किला विशेष में से रास्ता की मांग करने का अधिकारी नहीं है। अतः प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान अधिनियम अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एचम्

